SOCIO-ECONOMIC RESEARCH INSIGHTS
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
समाजिक-आर्थिक अनुसंधान अंतदृष्टि
सामाजिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका

SERI 2026; 1(1): 06 Received: 02-02-2026 Accepted: 03-02-2026

केंद्रीय बजट 2026–27 एवं बिहार के लिए उम्मीदें

रघुवर नाथ झा
अध्यक्ष
गोपी नाथ अकादमिक शोध संस्थान एवं प्रतिष्ठान(एन0जी0ओ0)
निदेशक
सामाजिक–आर्थिक अनुसंधान अकादमी
आर. एच. एम. टी. रोड. बरारी, भागलपुर– 812003
मो0 न0– 9470875223, 9939876418

सार

आम बजट 2026–27 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों में एकीकृत प्रावधान किए गये हैं, किसानों के लिए बहुभाषी एआइ टूल ''भारत विस्तार'' लांच किया जाएगा, आइ मिशन और नेश्नल क्वांटम मिशन के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है। 12.2 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान एआई–संबंधी नवाचारों को गति देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए 20 वर्षों की टैक्स हॉलीडे योजना का ऐलान किया, भारत में स्थिर टैक्स सेंटर के जरिये दुनियाभर के ग्राहकों को क्लाइड सेवाएं देनेवाली विदेशी कंपनियां वर्ष 2047 तक टैक्स छूट की पात्र होगी, हालांकि ऐसी कंपनियों को भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए भारत में रजिस्टर्ड किसी स्थानीय रिसेलर के माध्यम से काम करना होगा। केंद्रीय बजट 2026–27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 1,39,289 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया, हर जिले में स्टेम शिक्षा से जुड़े गर्ल्स हॉस्टल बनाए जायेंगे 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स के लिए आइआइएम के सहयोग से ट्रेनिंग कोर्स शुरू होंगें, 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स टेक्नोलॉजी सहयोगी होगी। इसे ऑरेंज इकोनॉमी कहा जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026–27 में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरूआत की घोषणा की गयी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए बजट आवंटन को 40,000 करोड़ रूपये तक बढ़ाया गया है, आइएसएम 2.0 से उपकरण, सामग्री उत्पादन, पूर्ण स्टैंक भारतीय आइपी डिजाइन अैर सप्लाई चैन को मजबूत किया जाएगा।

शब्दकुंजीः– *आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ''भारत विस्तार'', आइ मिशन, क्वांटम मिशन, ऑरेंज इकोनॉमी, सेमीकंडक्टर मिशन।*

विषय प्रवेशः–

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तुत किया गया आम बजट भारत के लिए लॉन्ग–टर्म ग्रोथ वाला बजट कह सकते हैं, यानी वो दवा, जो अभी नहीं, मगर धीरे–धीरे अपना असर दिखायेगी, जैसा कि पहले से पांच चुनावी राज्यों के मद्येनजर कयास लगाये जा रहे थे, वैसा कोई भी चुनावी चॉकलेट इसमें दिखाई नहीं पड़ा।

अलबत्ता सरकार का पूरा जोर विकास की रफ़्तार को स्थिर रखते हुए शिक्षा, रोजगार, नवाचार, व आर्थिक सुधारों पर रहा, समझा जा रहा है कि इसी के बलबूते हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकेगें।

निरंतरता और स्थिरताः— सरकार ने इस बजट के माध्यम से संदेश दिया है कि आर्थिक नीतियों में स्थिरता बनी रहेगी बुनियादी ढांचे पर 12.2 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश यह बताता है कि सरकार लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सड़क, रेल और लॉजिस्टिक्स को अपनी प्राथमिकता मानती है, यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

भविष्य की तकनीक पर दांवः— बजट का सबसे बड़ा संदेश नवाचार है इसमें सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 डिजिटल इंडिया पर जोर और एआइ के लिए विशेष प्रावधान बताते हैं कि भारत अगली औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करना चाहता है, बायोफार्मा शक्ति और रेयर अर्थ कॉरिडोर जैसी पहल दिखाती हैं कि भारत अब भविष्य के उद्योगों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।

समावेशी विकासः— नारी शक्ति और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित योजनाओं के साथ बजट यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि विकास का लाभ केवल शहरों तक सीमित न रहे, वित्तीय घाटे को 4.3 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य यह संदेश देता है कि सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ खिलवाड़ किये बिना विकास करना चाहती है।

बजट की मुख्य कार्य योजनाः—

1. उत्पादकता को बढ़ावाः—

उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए बजट में बायो—फार्मा शक्ति, सेमीकंडक्टर मिशन, रेयर अर्थ कॉरिडोर, कंटेन निर्माण योजना, टेक्सटाइल पार्कों, रासायनिक पार्कों की स्थापना और राष्ट्रीय फाइबर योजना सहित कई ऐलान किए गए है।

2. आकांक्षाएं पूरी करनाः—

लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमता निर्माण ताकि समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सके। इसके लिए तीन आयुर्वेदिक एम्स, पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप, माउंटेन ट्रेल, नॉलेज ग्रिड समेत कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया।

3. सबका विकासः—

सबका साथ, सबका विकास के कर्तव्य अमृत सरोवरों का निर्माण, चंदन—अखरोट व काजू जैसी उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन, शी—मार्ट, दिव्यांग कौशल योजना, पूर्वोदय योजना, बहु भाषायी एआई टूल—भारत विस्तार योजना की घोषणा की गई।

छह प्रमुख स्तंभः

1. आर्थिक वृद्धि के लिए विनिर्माण को गतिः—

आर्थिक विकास को गति देने के लिए बायो आर्थिक विकास को गति देने के लिए फार्मा शक्ति, सेमीकंडक्टर मिशन, रेयर अर्थ कॉरिडोर, कंटेन निर्माण योजना, टेक्सटाइल पार्कों, रासायनिक पार्कों की स्थापना और राष्ट्रीय फाइबर योजना सहित कई ऐलान किया गया।

2. विकास के आधारों पर सुदृढ़ीकरणः—

पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले टियर—2 और टियर—2 शहरों के विकास पर खास ध्यानदियाजाना है। सोलर ग्लास में इस्तेमाल सोडियम एंटीमोनट के आयात पर बीसीडी छूट, बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर उत्पाद शुल्क में छूट और सात हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे अहम ऐलान भी इस दिशा में अहम कदम है।

3. जनहित से जुड़ी सुविधाओं पर जोरः—

उत्तर भारत में निमहांस 2 की स्थापना होगी। इसके अलावा रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, दिव्यांग सहारा योजना, सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना, स्वयं

सहायता उद्यमिता की स्थापना की जाएगी।

4. विश्वास आधारित शासन को बढ़ावाः–

कस्टम वेयर हाउसिंग फ्रेमवर्क को वेयरहाउस ऑपरेटर केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। भरोसेमंद लंबी आपूर्ति चेन वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्य किया जाएगा, जिससे आयातकों को कार्गों के हर बार सत्यापन की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

5. व्यापार और जीवन सुगमताः–

विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री के स्रोत पर कर संग्रह घटाकर दो फीसदी किया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का हर्जाना आयकर से मुक्त होगा। व्यापार सुगमता के लिए कई जरूरी प्रावधान हटाए या उत्पाद एवं सेवा पर शुल्क कम किया गया।

6. राज्यों को ज्यादा वित्तीय सहायताः–

16 वें वित्त आयोग के अनुरूप राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा। इससे ग्रामीण, शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन में मदद मिल सकेगी। कर्ज–जीडीपी अनुपात घटाकर 55.6 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव है।

❖ **महिलाओं के लिए विशेषः–**

शी–मार्ट योजना से कारोबार में मददः–

- महिलाओं की अगुवाई वाले समूह को मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों के साथ शामिल करते हुए बाजार से जाड़ने का प्रस्ताव।
- शी–मार्ट योजना की शुरूआत होगी। इसके तहत महिलाओं को अपने कारोबार स्थापित करने के लिए बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा कारोबार के लिए कम ब्याज पर ऋण भी मुहैया कराया जाएगा।

❖ **युवाओं के लिए विशेषः–**

स्कूल–कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगीः–

- 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी।
- आईआईटी, आईआईएससी में 10 हजार नई टेक फेलोशिप शुरू की जाएगी। इसमें एआई और डीप–टेक में शोध पर विशेष जोर होगा।

❖ **किसानों के लिए विशेषः–**

काजू, अखरोट, चंदन की खेती को बढ़ावाः–

- अखरोट, बादाम और पाइन नट्स के पुराने और कम उपज वाले बगानों को पुनर्जीवित किया जाएगा।
- 20 हजार से अधिक पशु–चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की गई।

बिहार के लिए उम्मीदेंः–

बिहार को समग्र विकास से जोड़ने का रोडमैप

केंद्रीय बजट 2026–27 बिहार को भारत की समग्र विकास यात्रा से जोड़ने का एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है। जहाज मरम्मत इकोसिस्टम से लेकर ईबसों तक, टेक्सटाइल पार्क से लेकर सी–मार्ट तक प्रत्येक पहल बिहार की अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। औद्योगिक पुनरूद्धार, कृषि नवाचार, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन विकास पर केंद्रित यह बजट बिहार की समावेशी वृद्धि की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

कृषि प्रधान और उभरते औद्योगिक राज्य के रूप में बिहार केंद्रीय बजट के प्रावधानों का लाभ उठाने की मजबूत स्थिति में है। प्राद्योगिकी एकीकरण, उत्पादकता वृद्धि और अवसंरचना विस्तार पर

बजट का फोकस बिहार को सामाजिक आर्थिक विकास को तेज करने का अवसर देता है। यह बजट कृषि एमएसआई, अवसंरचना और मानव संसाधन को सशक्त करने का एक व्यापक रोडमैप है। केंद्रीय बजट में पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज मरम्मत इकोसिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव है।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ेगीः–

बजट 2026–27 में बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इससे राज्य के वंचित वर्ग, युवा और उद्योगों के विकास के द्वार खुलेंगे। रोजगार पैदा होंगे। केंद्रीय बजट का मुख्य फोकस पूंजीगत निवेश से सात प्रतिशत उच्च आर्थिक विकास की दर हासिल करने का लक्ष्य है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें राज्य के किसान, युवा वर्ग, गरीब एवं महिलाओं तक संसाधनों की पहुंच की पहल शामिल है। बायो फार्मा शक्ति के तहत किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण जैविक दवाओं का विनिर्माण में मदद मिलेगी। बिहार अभी दवा निर्माण में आगे बढ़ रहा है। बजट के प्रावधानों से इसे गति मिलेगी। बिहार में खादी एवं ग्रामोद्योग की लंबी श्रृंखला है। राज्य सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पुराने औद्योगिक क्लस्टर का पुनर्जीवनः–

केंद्रीय बजट में पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना की भी घोषणा की गयी है। बिहार में कई पुराने और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्लस्टर मौजूद हैं और अपने पुनरूद्धार की बाट जोह रहे हैं। इन्हें नया जीवन देकर बिहार का औद्योगिक क्षेत्र और तेजी से बढ़ सकता है। पिछले दिनों राज्य में इथनॉल, सीमेंट, टेक्सटाइल, बैग, जूता–चप्पल, साफ्ट ड्रिंक, पेपर, रिसाइकिल पेपर, रबड़, प्लास्टिक, वाटर, सप्लाई सामग्री, नमकीन–मिक्सचर, गुड़ आदि की फैक्ट्रीयां लगी है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, इंजिनीयरिंग, उर्जा, टेक्टाइल, आईटी, लघु विनिर्माण, पर्यटन एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से निवेश आ रहा है।

मॉड्यूलर रिएक्टर बिजली घरः–

केंद्र सरकार के सहयोग से बिहारमें परमाणु बिजली घर बनाने के लिए अब डीपीआर बनाने के लिए आवश्यक कारवाई शुरू की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वित्तीय वर्ष 2027–28 से परमाणु बिजली घर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक से बिहार में बिजली घर बनेंगे। इस तकनीक को परमाणु बिजली घर में सबसे सुरक्षित व कुशल माना जाता है। परमाणु बिजली घर बनने से बिहार को भविष्य में खपत होने वाली बिजली की जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्षः–

इस प्रकार यह बजटराज्यों में कारोबार, रोजगार और यातायात की गति तेज होगी। निवेश और अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिहार बायो फार्मा का हब बनेगा। बिहार को आवधारणा और नीतिगत प्रावधानों का लाभ मिलेगा। छः नए जलमार्ग विकसित होंगे। माल परिवहन सस्ता एवं सुगम होगा। अंतर्देशी व्यापार को बल मिलेगा। खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा मिलेगा।राज्य में उद्यम मार्ट खुलने का माग प्रशस्त होगा एवं पशुपालन –मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की आय वृद्धि में सहायक होगा।

संदर्भः–

- दैनिक जागरण
- दैनिक भास्कर
- हिन्दुस्तान
- द हिंदू
- द टाइम्स ऑफ इण्डिया

- प्रभात खबर
- अमर उजाला
- नव भारत टाइम्स
- नई दुनियां